भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 190

12 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

स्मार्ट-पीडीएस का कार्यान्वयन

190. श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (स्मार्ट-पीडीएस) में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अब तक स्मार्ट-पीडीएस प्रणाली को अपनाने वाले राज्यों के नाम क्या हैं तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया में इन राज्यों के समक्ष क्या चुनौतियां आई हैं;

(ग) देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने हेतु स्मार्ट-पीडीएस योजना के प्राथमिक उद्देश्य क्या हैं;

(घ) स्मार्ट-पीडीएस के तहत आधुनिकीकरण से संबंधित प्रयासों से कितने प्रतिशत आबादी को लाभ मिलने की संभावना है;

(ड.) क्या सरकार ने स्मार्ट-पीडीएस के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना और इंटरनेट सम्पर्क को सुदृढ़ करने के लिए धनराशि आवंटित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि सीमित डिजिटल सुविधा वाले दूरदराज या ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थी स्मार्ट-पीडीएस से लाभान्वित हो सकें; और

(छ) क्या सरकार ने स्मार्ट-पीडीएस के कार्यान्वयन में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए हैं और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (छ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

लोक सभा में दिनांक 12 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. *190 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): यह विभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उन्नत एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला सॉफ्टवेयर के विकास और कार्यान्वयन के लिए नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी द्वारा आधुनिकीकरण और सुधार के लिए स्कीम (स्मार्ट-पीडीएस) को कार्यान्वित कर रहा है। वर्तमान में, स्मार्ट-पीडीएस विकास के चरण में है। यह परियोजना एनआईसी द्वारा अक्टूबर 2024 से शुरू की गई थी और अप्रैल 2025 से चरणबद्ध तरीके से एप्लिकेशन के लॉन्च होने की उम्मीद है। इसमें महाराष्ट्र राज्य भी शामिल है।

(ख): इस विभाग ने स्मार्ट-पीडीएस स्कीम के लिए 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (तमिलनाडु को छोड़कर, जो प्रक्रियाधीन है) के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान में, स्मार्ट पीडीएस का विकास प्रगति पर है।

(ग): स्मार्ट-पीडीएस स्कीम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में प्रौद्योगिकी अवसंरचना को सुदृढ़ करने की परिकल्पना की गई है ताकि एनएफएसए और राज्य स्कीमों को कवर करते हुए समस्त पीडीएस इकोसिस्टम में प्रौद्योगिकी आधारित सुधार और परिवर्तनकारी बदलाव लाया जा सके। इस प्रकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की कार्यप्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों को बनाए रखने के लिए स्मार्ट-पीडीएस शुरू किया गया है, ताकि आईटी हार्डवेयर,सॉफ्टवेयर के संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीडीएस प्रचालनों की राज्य स्तरीय तकनीकी सीमाओं को दूर किया जा सके और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीडीएस से संबंधित सभी प्रचालनों को कवर करने वाली एक एकीकृत केंद्रीय प्रणाली को संस्थापित किया जा सके।

(घ): स्मार्ट पीडीएस प्रणाली के आधुनिकीकरण के प्रयासों से देश के सभी पीडीएस लाभार्थियों को लाभ प्राप्त होता है। वर्तमान में, एनएफएसए के तहत 81.35 करोड़ के कुल अपेक्षित कवरेज की तुलना में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत 80.56 करोड़ व्यक्ति निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं, जो कुल कवरेज का लगभग 99.03% है।

(ड.): इस स्कीम को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए 349.9 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ लागू किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत, स्मार्ट-पीडीएस के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी क्षेत्रों में क्लाउड अवसंरचना का लाभ उठाकर मौजूदा सर्वर/डाटा केंद्रों को प्रतिस्थापित करने का प्रावधान किया गया है।

...2/-

(च): कुछ राज्यों में दूरदराज के स्थानों/शैडो/नेटवर्क रहित क्षेत्रों में उचित दर दुकानों पर ईपीओएस उपकरणों की इंटरनेट/कनेक्टिविटी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, दूरसंचार विभाग से इंटरनेट/कनेक्टिविटी से संबंधित मुद्दों का समाधान करने का अनुरोध किया गया है। एक देश एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) के तहत लाभार्थियों को किसी भी प्रचालनात्मक ईपीओएस उपकरण युक्त उचित दर दुकान से किसी इंटरनेट/कनेक्टिविटी से संबंधित चुनौतियों का सामना किए बिना अपनी पात्रता के खाद्यान्न का उठान करने का अधिकार दिया गया है। ईपीओएस उपकरणों में सीमित/बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऑफ़लाइन पद्धति में काम करने की कार्यक्षमता है। ऑफलाइन ईपीओएस डाटा को पीडीएस ऑनलाइन प्रणाली के साथ सिंक करने के लिए ईपीओएस उपकरणों को समय-समय पर नेटवर्क क्षेत्र में आना पड़ता है।

(छ): राज्य परामर्श/प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अधिकारियों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 12.03.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या *190 के उत्तर के भाग (छ) में उल्लिखित अनुबंध

राज्य परामर्श/प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अधिकारियों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण।

दिनांक	राज्य सरकार/एनआईसी/ अन्य हितधारक	गतिविधि
30-सितम्बर-24	एफसीआई	डिपो ऑनलाइन सिस्टम का प्रदर्शन
07-अक्तूबर-24	क्लाउड सेवा प्रदाता	समाधान पर क्लाउड सेवा प्रदाता टीम के साथ तकनीकी चर्चा
08-अक्तूबर-24	एनआईसी हैदराबाद	ईपीओएस सिस्टम का डेमो
09-अक्तूबर-24	एनआईसी हैदराबाद	एडमिन लॉगिन से ईपीओएस पोर्टल का डेमो
10-अक्तूबर-24	तमिलनाडु	तमिलनाडु पीडीएस का प्रदर्शन
11-अक्तूबर-24	गुजरात	गुजरात पीडीएस का प्रदर्शन
11-अक्तूबर-24	क्लाउड सेवा प्रदाता	डाटाबेस पर क्लाउड सेवा प्रदाता टीम के साथ तकनीकी चर्चा
14-अक्तूबर-24	छत्तीसगढ	छत्तीसगढ़ पीडीएस का प्रदर्शन
15-अक्तूबर-24	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश पीडीएस का प्रदर्शन
16-अक्तूबर-24	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश पीडीएस का प्रदर्शन
17-अक्तूबर-24	पुडुचेरी	पुडुचेरी पीडीएस का प्रदर्शन
17-अक्तूबर-24	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश पीडीएस का प्रदर्शन
18-अक्तूबर-24	केरल	केरल पीडीएस का प्रदर्शन
19-अक्तूबर-24	हरियाणा	हरियाणा पीडीएस का प्रदर्शन
21-अक्तूबर-24	पंजाब	पंजाब पीडीएस का प्रदर्शन
22-अक्तूबर-24	कर्नाटक	कर्नाटक पीडीएस का प्रदर्शन
22-अक्तूबर-24	दिल्ली	दिल्ली पीडीएस का प्रदर्शन
23-अक्तूबर-24	झारखंड	झारखंड पीडीएस का प्रदर्शन
23-अक्तूबर-24	बिहार	बिहार पीडीएस का प्रदर्शन
23-अक्तूबर-24	एनआईसी बैंगलोर	ब्लॉकचेन पर चर्चा
24-अक्तूबर-24	तेलंगाना	तेलंगाना पीडीएस का प्रदर्शन
24-अक्तूबर-24	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश पीडीएस का प्रदर्शन
25-अक्तूबर-24	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल पीडीएस का प्रदर्शन
26-अक्तूबर-24	राजस्थान	राजस्थान पीडीएस का प्रदर्शन
28-अक्तूबर-24	ओडिशा	ओडिशा पीडीएस का प्रदर्शन
28-अक्तूबर-24	असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम	पूर्वोत्तर राज्यों के साथ पीडीएस पर चर्चा
29-अक्तूबर-24	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल पीडीएस का प्रदर्शन
13-नवंबर-24	एफसीआई	डिपो ऑनलाइन प्रणाली डॉक्यूमेंटेशन पर एफसीआई के साथ बैठक

...2/-

06-दिसंबर-24	आंध्र प्रदेश (हैदराबाद स्थान)	राज्य एनआईसी, विकास टीम और अन्य अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत बैठक
07-दिसंबर-24	कर्नाटक (बैंगलोर स्थान)	राज्य एनआईसी और अन्य अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत बैठक
09-दिसंबर-24	कर्नाटक (बैंगलोर स्थान)	पीडीएस सिस्टम का व्यक्तिगत अध्ययन
09-दिसंबर-24	उत्तर प्रदेश (कानपुर)	एनआईसी टीम के साथ जिला स्तर पर आरसीएमएस की कार्यप्रणाली पर चर्चा
27-जनवरी-25	चंडीगढ़	एनआईसी टीम के साथ डीबीटी प्रवाह के प्रक्रिया मानचित्रों का प्रदर्शन
28-जनवरी-25	दिल्ली	एनआईसी टीम के साथ डीबीटी प्रवाह पर चर्चा
29-जनवरी-25	उत्तर प्रदेश	एनआईसी टीम द्वारा खरीद मॉड्यूल का प्रदर्शन
29-जनवरी-25	पश्चिम बंगाल	एनआईसी टीम द्वारा आरसीएमएस, एफपीएस और खरीद मॉड्यूल का प्रदर्शन
30-जनवरी-25	उत्तर प्रदेश	खरीद मॉड्यूल पर चर्चा और स्पष्टीकरण के लिए बैठक
30-जनवरी-25	केरल	शिकायत मॉड्यूल का प्रदर्शन
30-जनवरी-25	चंडीगढ़	डीबीटी प्रवाह पर चर्चा
20-फ़रवरी-25	सिक्किम	नए विकसित आरसीएमएस और एफपीएस मॉड्यूल का प्रदर्शन
20-फ़रवरी-25	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	नए विकसित आरसीएमएस और एफपीएस मॉड्यूल का प्रदर्शन
20-फ़रवरी-25	आंध्र प्रदेश	नए विकसित आरसीएमएस और एफपीएस मॉड्यूल का प्रदर्शन
24-फ़रवरी-25	अरुणाचल प्रदेश	नए विकसित आरसीएमएस और एफपीएस मॉड्यूल का प्रदर्शन
03-मार्च-25	असम	नए विकसित आरसीएमएस और एफपीएस मॉड्यूल का प्रदर्शन
03-मार्च-25	मणिपुर	नए विकसित आरसीएमएस और एफपीएस मॉड्यूल का प्रदर्शन
03-मार्च-25	मेघालय	नए विकसित आरसीएमएस और एफपीएस मॉड्यूल का प्रदर्शन
04-मार्च-25	मिजोरम	नए विकसित आरसीएमएस और एफपीएस मॉड्यूल का प्रदर्शन
04-मार्च-25	नागालैंड	नए विकसित आरसीएमएस और एफपीएस मॉड्यूल का प्रदर्शन
04-मार्च-25	गोवा	नए विकसित आरसीएमएस और एफपीएस मॉड्यूल का प्रदर्शन
04-मार्च-25	अरुणाचल प्रदेश	विकसित आरसीएमएस और एफपीएस मॉड्यूल की राज्य टीम द्वारा यूएटी
05-मार्च-25	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	विकसित आरसीएमएस और एफपीएस मॉड्यूल की राज्य टीम द्वारा यूएटी

*****